

(b) what is the amount of relief sanctioned by the Central Government to Assam; and

(c) whether the relief measures taken by State are adequate?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA):

(a) During recent floods in Assam, a total area of about 1,21,000 hectares including 29,600 hectares of cropped area have been affected.

(b) A total amount of Rs. 11.25 crores, out of Rs. 22.5 crores allocated by the Centre in the current year under Calamity Relief Fund for relief operations in the wake of natural calamities including floods, has been released to the State Government.

(c) Adequate relief measures on immediate basis have been provided.

गुजरात में सार्वजनिक नलकूपों का लगाया जाना

3488. श्री रामसिंह राठवा : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में विश्व बैंक की सहायता से सार्वजनिक नलकूप लगाये जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक से मिली सहायता का वर्ष-वार व्यौरा क्या है ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान विश्व बैंक की सहायता से किन-किन स्थानों पर वे नलकूप लगाए गए ; और

(ङ) वर्ष 1992 में विश्व बैंक की सहायता से राज्य में कितने नलकूप लगाए जाने का प्रस्ताव है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) (क) जी, नहीं ।

(ग) गुजरात सरकार ने सिंचाई नलकूपों के निर्माण के लिए विश्व बैंक सहायता अब तक प्राप्त नहीं की है ।

(ख), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

राजस्थान सरकार द्वारा टिहरी बांध के जल में अपने हिस्से की मांग

3489. श्री शिव चरण सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार ने टिहरी बांध से कितने जल का हिस्सा मांगा है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार कितना जल उपलब्ध करायेगी और ऐसा कब तक किया जाएगा ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है !

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग) राजस्थान सरकार ने राजस्थान में क्षेत्रों के लिए टिहरी बांध परियोजना जल का 10 प्रतिशत आवंटित करने के वास्ते उत्तर प्रदेश सरकार को राजी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को एक पत्र लिखा है। तदनुसार यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार के साथ उठाया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राजस्थान सरकार को जुलाई, 1988 में तथा इस मंत्रालय को सितम्बर, 1988 में सूचित किया कि टिहरी बांध परियोजना पर गंगा जल की वचनबद्धताओं को देखते हुए राजस्थान के क्षेत्रों के लिए जल आपूर्ति करना संभव प्रतीत नहीं हुआ। राजस्थान सरकार को अक्टूबर 1988 में सलाह दी गयी कि वह यह मामला यमुना पर अन्तर्राष्ट्रीय बैठक के समक्ष लाए। यमुना विवाद पर विचार करने के लिए जल संसाधनों में अन्तर्राष्ट्रीय

मुद्दों पर स्थायी समिति की बैठक सितम्बर, 1990 में आयोजित की गयी थी परन्तु इस मुद्दे पर विचार नहीं हो पाया। किन्तु राजस्थान की जल-आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली हिमालयी नदियों के अधिशेष प्रवाहों को पश्चिम की ओर मोड़ने का सामान्य मुद्दा राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की बैठकों में राजस्थान द्वारा अलग से उठाया गया। यह निर्णय लिया गया कि 8वीं योजना अवधि के दौरान इस पहलू पर अध्ययन पूरे किए जाएं। तदनुसार राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने ये अध्ययन शुरू किए हैं।

जल-संसाधनों का उपयोग

3490. श्री अजुमाई ए० परमार : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चल रहे जल विवादों के कारण जल संसाधनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है; और

(ख) सरकार राष्ट्र हित में जल संसाधनों का समुचित उपयोग करने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) चूंकि जल विवाद, कुल उपलब्ध जल में हिस्से का निर्णय करने के लिए है इसलिए इस समय चल रहे जल विवाद का जल संसाधनों के उपयोग पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तथापि, कभी कभी जल संसाधन परियोजनाओं के शीघ्र पूरा करने पर इसका प्रभाव पड़ जाता है।

(ख) सरकार ने वर्ष 1987 से राष्ट्रीय जल नीति तैयार की है। देश में जल संसाधनों के विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार करने तथा राष्ट्रीय संसाधन परिषद की प्रगति की सूचना देने के वास्ते राष्ट्रीय जल नीति के अन्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए एक राष्ट्रीय जल बोर्ड सितम्बर, 1990 में गठित किया गया है।

Functions of Water and Power Consultancy Services (India) Limited (WAPCOS)

3491. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) what are the functions and objectives of WAPCOS;

(b) what is the annual budget sanctioned for it stating the details during the last three years;

(c) whether WAPCOS has suggested any water harnessing and storage projects for Andhra Pradesh; and

(d) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI V. C. SHUKLA): (a) WAPCOS is a premier Consultancy Organisation in the field of Water Resources and Power Department sharing latest technical know-how with other developing countries and with Clients within the country. WAPCOS acts as a nodal agency to project India's experience and expertise in related areas world-wide.

(Rs in Lakhs)

Particulars	Year		
	1990-91	1991-92	1992-93
Revenue Budget			
Income	746.94	984.41	1088.92
Expenditure	616.02	808.48	892.13
Profit before Tax	130.92	175.93	196.79
Capital Budget	89.60	97.35	181.77